

ज्यादा धन होने का मतलब ज्यादा सुखी होना नहीं है

## राजनीतिक निर्लज्जता

भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना सत्ता के लोधे में जिस तरह गट्टवारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाने की ओर पर बढ़ चली है उससे अवसरावादी निर्णय का एक और शर्मनाक उदाहरण ही पेश होगा जो रहा है। वैसे तो देश में कई भी ऐसा दल नहीं जो अवसरावादी राजनीति से अद्युता हो, लेकिन जो शिवसेना कर रहा है वह राजनीतिक निर्णय की पराकारी है। हिंदुत्व की राजनीति का दम भरने और कांग्रेस एवं गट्टवारी कांग्रेस पार्टी को संदेश कोसें वाली शिवसेना यही साबित कर रही है कि वह सत्ता के लिए किसी भी हड तक सकती है। वह ऐसे सबके अपनी रीत-नीति को धूता बताकर कांग्रेस और गट्टवारी कांग्रेस पार्टी को गले लाना जो रही है जब अयोध्या फैसला आने के बाद देश उन दलों का स्पर्धन कर रहा है जो राम मंदिर निर्माण की ओर आधिकारी और विशेष किया करते थे। वह दूप्रभ करता है कि शिवसेना अयोध्या मालौ में कांग्रेस और गट्टवारी कांग्रेस पार्टी के खंडे को इन्हीं आसानी से भूला पसंद कर रही है? शिवसेना अपने सत्ता लोधे में खुट को बाला साहब टाकरे की विरोध से ही अलग नहीं कर रही है, उस कांग्रेस के समक्ष नतमतक भी हो रही है जिसके विरोध से ही उसका जम्हुआ था। निःसंदेश शिवसेना को सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन क्या उसके नेता खुद से और साथ ही अपने प्रतिवद समर्थकों से आंख मिला पाएगे? क्या उसकी राजनीति में नीति के लिए कई स्थान नहीं? क्या अब वह कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ-साथ समान नागरिक सहित और ऐसे ही अन्य मसलों पर वही सब कुछ कहा करेगी जो कांग्रेस और गट्टवारी कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है?

शिवसेना इस आधार पर गट्टवारी जननीतिक घटनाएं से अलग हुई, क्योंकि भाजपा ने बारी-बारी से दोनों दलों के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की उसकी मांग नहीं मारी, लेकिन उसे स्पष्ट करना चाहिए कि आधिकारी ऐसी कोई सहमति बनी ही की क्या? स्वाल यह भी है कि क्या यह दृढ़-दृढ़ साल तक दोनों दलों के नेताओं को और से मुख्यमंत्री पद संभालना एक-दूसरे के प्रति भरोसे का परियाक छोड़ा? एक-दूसरे के प्रति अवश्यक से भरा यह फार्मूला तो नाकामी की ही कहानी लिखता। यह समझ आता है कि शिवसेना इससे कुंठित है कि वह भाजपा के मुकाबले कमज़ोर हो गई है, लेकिन क्या उसका उपर धूरी विशेषी दलों की गोद में बैठना ही सकता है? समझना कठिन है कि शिवसेना अनुभवीन आदित्य टाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर क्यों आमदार है? वैसे तो शिवसेना परिवर्वाद की राजनीति का ही पोषण कर रही है, लेकिन अब तो वह लोक लाज त्यागकर धोर वंशावादी दल बन रही है।

## चुनाव और पर्यावरण

झारखंड हाई कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर चुनाव में इसके फ्रेंडली सामग्री के इस्तेमाल का आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराए जाने की मांग वाली वाचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रचार क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। यह आदेश भी अद्यता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल होना है। इससे इनकार नहीं होता कि इसके जासकता कि इसमें से कई सामग्री इसके फ्रेंडली नहीं होती बैनर-पोस्टर से लेकर होर्डिंग, प्लॉकेस, प्लास्टिक की लड़ियां, बोतल, ग्लास आदि किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे जागरूकता की कमी कहें अथवा लापरवाही, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों इस हटने की जहानपत नहीं तात्पती। विभिन्न चुनावी समाजों, बैठकों, छोटी-बड़ी रैलियों आदि में संबंधित स्थलों के अलावा पूरा शहर ऐसी सामग्री से पह जाता है। हाईकोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है।

चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अदालत का यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। यह आदेश भी अद्यता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल होना है। इससे इनकार नहीं होता कि इसके जासकता कि इसमें से कई सामग्री इसके फ्रेंडली नहीं होती बैनर-पोस्टर से लेकर होर्डिंग, प्लॉकेस, प्लास्टिक की लड़ियां, बोतल, ग्लास आदि किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे जागरूकता की कमी कहें अथवा लापरवाही, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों इस हटने की जहानपत नहीं तात्पती। विभिन्न चुनावी समाजों, बैठकों, छोटी-बड़ी रैलियों आदि में संबंधित स्थलों के अलावा पूरा शहर ऐसी सामग्री से पह जाता है। हाईकोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है।

आज जब धूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चर्चित है, जूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने प्रचार-प्रसार में ऐसी सामग्री का कर्तव्य प्रयोग न करें, जो पर्यावरण के लिए किसी न किसी रूप में घाटक हैं। आवश्यकता है कि भारत निवाचन आयोग इस दिशा में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे। साथ ही, इसकी नियमणी भी सक्षम प्रधिकारों से सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन राजनीतिक दल और उपायोद्वारा कर रहे हैं अथवा नहीं, आयोग भी अपने तंत्र के माध्यम से इसका औचक निरीक्षण कर सुनिश्चित करें। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को भी इसकी जावाबदेही सीधी जारी काहिए। आवश्यकता है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन ईमानदारी से हो, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सकते।

चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अदालत का यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। यह आदेश भी अद्यता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल होना है। इससे इनकार नहीं होता कि इसके जासकता कि इसमें से कई सामग्री इसके फ्रेंडली नहीं होती बैनर-पोस्टर से लेकर होर्डिंग, प्लॉकेस, प्लास्टिक की लड़ियां, बोतल, ग्लास आदि किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे जागरूकता की कमी कहें अथवा लापरवाही, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों इस हटने की जहानपत नहीं तात्पती। विभिन्न चुनावी समाजों, बैठकों, छोटी-बड़ी रैलियों आदि में संबंधित स्थलों के अलावा पूरा शहर ऐसी सामग्री से पह जाता है। हाईकोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है।

चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अदालत का यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। यह आदेश भी अद्यता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल होना है। इससे इनकार नहीं होता कि इसके जासकता कि इसमें से कई सामग्री इसके फ्रेंडली नहीं होती बैनर-पोस्टर से लेकर होर्डिंग, प्लॉकेस, प्लास्टिक की लड़ियां, बोतल, ग्लास आदि किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे जागरूकता की कमी कहें अथवा लापरवाही, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों इस हटने की जहानपत नहीं तात्पती। विभिन्न चुनावी समाजों, बैठकों, छोटी-बड़ी रैलियों आदि में संबंधित स्थलों के अलावा पूरा शहर ऐसी सामग्री से पह जाता है। हाईकोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है।

चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अदालत का यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। यह आदेश भी अद्यता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल होना है। इससे इनकार नहीं होता कि इसके जासकता कि इसमें से कई सामग्री इसके फ्रेंडली नहीं होती बैनर-पोस्टर से लेकर होर्डिंग, प्लॉकेस, प्लास्टिक की लड़ियां, बोतल, ग्लास आदि किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे जागरूकता की कमी कहें अथवा लापरवाही, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों इस हटने की जहानपत नहीं तात्पती। विभिन्न चुनावी समाजों, बैठकों, छोटी-बड़ी रैलियों आदि में संबंधित स्थलों के अलावा पूरा शहर ऐसी सामग्री से पह जाता है। हाईकोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है।

चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अदालत का यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। यह आदेश भी अद्यता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल होना है। इससे इनकार नहीं होता कि इसके जासकता कि इसमें से कई सामग्री इसके फ्रेंडली नहीं होती बैनर-पोस्टर से लेकर होर्डिंग, प्लॉकेस, प्लास्टिक की लड़ियां, बोतल, ग्लास आदि किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे जागरूकता की कमी कहें अथवा लापरवाही, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों इस हटने की जहानपत नहीं तात्पती। विभिन्न चुनावी समाजों, बैठकों, छोटी-बड़ी रैलियों आदि में संबंधित स्थलों के अलावा पूरा शहर ऐसी सामग्री से पह जाता है। हाईकोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है।

चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ऐसी सामग्री क